

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS ***CURRENT*** ***AFFAIRS***

In Bilingual

28 & 29 June 2026



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: Under RBI's proposed framework, which entities will be allowed to participate in the term money market as both borrowers and lenders?

प्रश्न: RBI के प्रस्तावित ढांचे के तहत किन संस्थाओं को टर्म मनी मार्केट में उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी?

- A) Only Commercial Banks / केवल वाणिज्यिक बैंक
- B) NBFCs, HFCs and Financial Institutions / NBFCs, HFCs एवं वित्तीय संस्थान
- C) Only Corporate Companies / केवल कॉर्पोरेट कंपनियां
- D) Mutual Funds and Insurance Companies / म्यूचुअल फंड एवं बीमा कंपनियां
- E) Foreign Banks Only / केवल विदेशी बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed expanding the term money market to include Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and other financial institutions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने टर्म मनी मार्केट का दायरा बढ़ाकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- Under the proposed framework, all Indian Financial Institutions, NBFCs and Housing Finance Companies (HFCs) will be allowed to participate as both borrowers and lenders.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों, NBFCs तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) को उधारकर्ता एवं ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- Companies will be permitted to participate only as lenders in the term money market.
- कंपनियों को टर्म मनी मार्केट में केवल ऋणदाता (Lender) के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।
- At present, only banks and standalone primary dealers are allowed to participate in the term money market.
- वर्तमान में केवल बैंक एवं स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को ही टर्म मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति है।
- The RBI has invited stakeholder comments and feedback on the proposal until 17 July 2026.
- RBI ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों से 17 जुलाई 2026 तक सुझाव एवं टिप्पणियाँ मांगी हैं।
- The move aims to improve liquidity conditions and provide an alternative source of short-term funding to market participants.





- इस कदम का उद्देश्य तरलता (Liquidity) में सुधार करना तथा बाजार सहभागियों को अल्पकालिक वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है।
- RBI stated that a more active term money market would strengthen monetary policy transmission by linking overnight interest rates with longer-term interest rates.
- RBI के अनुसार अधिक सक्रिय टर्म मनी मार्केट, ओवरनाइट ब्याज दरों और दीर्घकालिक ब्याज दरों के बीच बेहतर संबंध स्थापित कर मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) को मजबूत करेगा।

About Term Money Market | टर्म मनी मार्केट के बारे में

- The Term Money Market is a segment of the money market where funds are borrowed and lent for periods exceeding 14 days and up to one year.
- टर्म मनी मार्केट मनी मार्केट का वह खंड है जिसमें 14 दिनों से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए धन उधार लिया और दिया जाता है।
- It helps financial institutions manage short-term liquidity requirements.
- यह वित्तीय संस्थानों को अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता करता है।

Static GK

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI का मुख्यालय – मुंबई
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा





Recent News Headlines Related to RBI

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed allowing a wider set of participants to access the Term Money Market.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने टर्म मनी मार्केट में अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank of India (Responsible Lending Conduct and Customer Protection) Directions, 2026.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन डायरेक्शंस, 2026" जारी किए हैं।
- The Reserve Bank of India (RBI) has permitted Indian banks, including their overseas branches, to extend loans against FCNR(B) deposits.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकों तथा उनकी विदेशी शाखाओं को FCNR(B) जमा के विरुद्ध ऋण देने की अनुमति दी है।
- The Reserve Bank of India has issued the final revised Kisan Credit Card (KCC) Framework.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ढांचा जारी किया है।
- The Reserve Bank of India has exempted banks from maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) on fresh Non-Resident External (NRE) Term Deposits with a maturity of 3 years or more.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली नई अनिवासी बाह्य (NRE) सावधि जमा पर नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने से छूट दी है।
- The Reserve Bank of India cancelled the licence of Shree Mahalaxmi Urban Co-operative Credit Bank, a Karnataka-based co-operative bank.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
- The Reserve Bank of India (RBI) relaxed the capital requirements for banks on loans backed by the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 5.0).





Ques: According to NPCI BHIM Services Limited (NBSL), BHIM is set to evolve into which type of platform?

प्रश्न: NPCI BHIM Services Limited (NBSL) के अनुसार, BHIM किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित होने जा रहा है?

- A) Digital Financial Services Platform / डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म
- B) Digital Banking Platform / डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म
- C) E-commerce Platform / ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
- D) Digital Investment Exchange / डिजिटल निवेश एक्सचेंज
- E) Cryptocurrency Payment Platform / क्रिप्टोकॉरेंसी भुगतान प्लेटफॉर्म

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- BHIM (Bharat Interface for Money), developed by NPCI BHIM Services Limited (NBSL), is set to evolve from a UPI payment app into a Digital Financial Services Platform.
- NPCI BHIM Services Limited (NBSL) द्वारा विकसित BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) अब केवल UPI भुगतान ऐप न रहकर डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित होने जा रहा है।
- According to Lalitha Nataraj, Managing Director & CEO of NBSL, BHIM will soon offer products such as credit cards, loans, pension schemes, insurance, and investments in partnership with banks and NBFCs.
- NBSL की प्रबंध निदेशक एवं CEO ललिता नटराज के अनुसार, BHIM जल्द ही बैंकों एवं NBFCs के सहयोग से क्रेडिट कार्ड, ऋण, पेंशन योजनाएँ, बीमा तथा निवेश जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- In May 2026, BHIM recorded 244 million monthly transactions.
- मई 2026 में BHIM पर 244 मिलियन मासिक लेनदेन दर्ज किए गए।
- The total transaction value on BHIM during May 2026 was ₹26,952 crore.
- मई 2026 में BHIM के माध्यम से कुल ₹26,952 करोड़ मूल्य के लेनदेन हुए।
- BHIM was developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) and was launched on 30 December 2016.
- BHIM का विकास नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया गया था और इसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- BHIM stands for Bharat Interface for Money.
- BHIM का पूर्ण रूप Bharat Interface for Money (भारत इंटरफेस फॉर मनी) है।
- BHIM Launch Date – 30 December 2016
- BHIM का शुभारंभ – 30 दिसंबर 2016
- National Payments Corporation of India (NPCI) Established – 2008
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्थापना – 2008
- NPCI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- NPCI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- UPI (Unified Payments Interface) is an instant real-time payment system developed by NPCI.
- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) NPCI द्वारा विकसित एक त्वरित रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है।

EXAM
Genius





Ques: RBI's holdings of Government Securities (G-Secs) rose to the highest level in how many years as of March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 तक RBI की सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में हिस्सेदारी कितने वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई?

- A) 5 Years / 5 वर्ष
- B) 8 Years / 8 वर्ष
- C) 10 Years / 10 वर्ष
- D) 13 Years / 13 वर्ष
- E) 15 Years / 15 वर्ष

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) increased its holdings of Government Securities (G-Secs) after conducting large-scale bond purchases, taking its share to a multi-year high.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद के बाद सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में अपनी हिस्सेदारी को कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।
- RBI's share in outstanding Government Securities increased from 14.5% at the end of December 2025 to 17.6% by the end of March 2026.
- दिसंबर 2025 के अंत में बकाया सरकारी प्रतिभूतियों में RBI की हिस्सेदारी 14.5% थी, जो मार्च 2026 के अंत तक बढ़कर 17.6% हो गई।
- This is the highest level of RBI's ownership of Government Securities in the last 13 years.
- यह पिछले 13 वर्षों में RBI की सरकारी प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी का उच्चतम स्तर है।
- RBI carried out large-scale Open Market Operations (OMOs) to inject durable liquidity into the banking system.
- RBI ने बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक तरलता (Liquidity) बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) किए।
- During the March quarter, RBI purchased Government Securities worth about ₹3.5 lakh crore through OMOs and around ₹90,000 crore through secondary market operations.





Ques: As per the RBI's final directions on the Trade Receivables Discounting System (TReDS), what is the minimum net worth required for entities providing discounting services?

प्रश्न: RBI द्वारा Trade Receivables Discounting System (TReDS) पर जारी अंतिम दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिस्काउंटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कितनी निर्धारित की गई है?

- A) ₹10 crore / ₹10 करोड़
- B) ₹15 crore / ₹15 करोड़
- C) ₹20 crore / ₹20 करोड़
- D) ₹25 crore / ₹25 करोड़
- E) ₹50 crore / ₹50 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) issued its final directions on the Trade Receivables Discounting System (TReDS) to simplify the system and improve access to working capital for MSMEs.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने MSMEs के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुँच को सरल एवं सुगम बनाने हेतु Trade Receivables Discounting System (TReDS) पर अपने अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए।
- RBI has prescribed a minimum net worth of ₹25 crore for entities providing discounting services under TReDS.
- RBI ने TReDS के तहत डिस्काउंटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए ₹25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ निर्धारित की है।
- The minimum net worth must be certified by a statutory auditor.
- निर्धारित न्यूनतम नेटवर्थ का वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा।
- Existing entities providing TReDS services have been given time until 31 March 2028 to comply with the prescribed net worth criterion.
- वर्तमान में TReDS सेवाएँ प्रदान कर रही संस्थाओं को 31 मार्च 2028 तक इस नेटवर्थ मानदंड का पालन करने की समय-सीमा दी गई है।
- Trade Receivables Discounting System (TReDS) is an online platform that enables MSMEs to auction their invoices or trade receivables to banks and financial institutions for faster realization of working capital.





Ques: Under which phase of PMGSY were road projects worth ₹211.71 crore approved for Tripura?

प्रश्न: त्रिपुरा के लिए ₹211.71 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को PMGSY के किस चरण के अंतर्गत मंजूरी दी गई?

- A) PMGSY-I
- B) PMGSY-II
- C) PMGSY-III
- D) PMGSY-IV
- E) PMGSY-V

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Rural Development approved road infrastructure projects worth ₹211.71 crore for Tripura under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-IV).
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत त्रिपुरा के लिए ₹211.71 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- The approved projects will cover more than 160 kilometres of rural roads across the State.
- स्वीकृत परियोजनाओं के तहत राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा।
- A total of 96 habitations will receive all-weather road connectivity for the first time.
- राज्य के 96 बस्तियों (Habitations) को पहली बार सर्व-ऋतु (All-weather) सड़क संपर्क सुविधा प्राप्त होगी।
- The initiative aims to improve rural connectivity, enhance access to education, healthcare and markets, and support socio-economic development.
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाना तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- PMGSY focuses on connecting eligible unconnected rural habitations through quality road infrastructure.
- PMGSY का उद्देश्य पात्र ग्रामीण बस्तियों को गुणवत्तापूर्ण सड़क अवसंरचना के माध्यम से जोड़ना है।





About PMGSY | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में

- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched on 25 December 2000 to provide all-weather road connectivity to eligible rural habitations.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को पात्र ग्रामीण बस्तियों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए की गई थी।
- PMGSY is implemented by the Ministry of Rural Development.
- PMGSY का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- PMGSY-IV focuses on providing connectivity to remaining eligible habitations and improving rural road networks.
- PMGSY-IV का उद्देश्य शेष पात्र बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करना तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना है।
- Rural roads play a crucial role in improving agricultural marketing, healthcare access and overall rural development.
- ग्रामीण सड़कें कृषि विपणन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा समग्र ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Static GK

- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Launched – 25 December 2000
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत – 25 दिसंबर 2000
- Current Union Minister of Rural Development – Shivraj Singh Chouhan
- वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री – शिवराज सिंह चौहान
- Capital of Tripura – Agartala
- त्रिपुरा की राजधानी – अगरतला
- Governor of Tripura – N. Indrasena Reddy
- त्रिपुरा के राज्यपाल – एन. इंद्रसेना रेड्डी
- Chief Minister of Tripura – Manik Saha
- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री – माणिक साहा





Recent News Headlines Related to Schemes

- The Prime Minister is scheduled to release the 23rd instalment of the PM-KISAN Scheme on 20 June 2026.
- प्रधानमंत्री 20 जून 2026 को PM-KISAN योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
- Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana aims to facilitate the creation of more than 3.5 crore jobs over a period of two years.
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है।
- Union Minister Jagat Prakash Nadda launched nationwide celebrations to commemorate a decade of the successful implementation of the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA).
- केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश (जेपी) नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के सफल क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया।
- The Kerala government launched the 'Priyadarshini' free travel scheme for women and transgender persons.
- केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'प्रियदर्शिनी' मुफ्त यात्रा योजना शुरू की है।
- The Government of India (GoI), through the Ministry of Finance (MoF), has extended the validity of the Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0 (CGSMFI-2.0) until 31 August 2026 or until guarantees worth ₹20,000 crore are issued, whichever is earlier.
- भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (MoF) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस-2.0 (CGSMFI-2.0) की वैधता 31 अगस्त 2026 तक या ₹20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक (जो पहले हो) बढ़ा दी है।
- ArcelorMittal Nippon Steel India has become the first company to receive approval for a Strategic Investment Plan under the PM-SETU Scheme.
- ArcelorMittal Nippon Steel India PM-SETU योजना के तहत स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है।





Ques: The Youth Co:Lab National Innovation Challenge 2026 is jointly led by UNDP India and which organization?

प्रश्न: यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 का संयुक्त नेतृत्व UNDP India और किस संगठन द्वारा किया जाता है?

- A) Citi Foundation / सिटी फाउंडेशन
- B) World Bank / विश्व बैंक
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) UNICEF / यूनिसेफ
- E) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Six youth-led startups from across India emerged as winners of the 8th edition of the Youth Co:Lab National Innovation Challenge 2026.
- भारत भर से 6 युवा-नेतृत्व वाले स्टार्टअप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण के विजेता बने।
- The initiative is jointly led by United Nations Development Programme (UNDP) India and the Citi Foundation.
- इस पहल का संयुक्त नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भारत और सिटी फाउंडेशन (Citi Foundation) द्वारा किया जाता है।
- It is organized in partnership with the Atal Innovation Mission (AIM) and implemented by the T-Hub Foundation.
- इसका आयोजन अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के सहयोग से किया जाता है तथा इसका कार्यान्वयन T-Hub Foundation द्वारा किया जाता है।
- The programme promotes youth-led innovation aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).
- यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप युवा-नेतृत्व वाले नवाचारों को बढ़ावा देता है।
- The winning startups received ₹3.5 lakh each as seed grants, while the runners-up received ₹2.2 lakh each.
- विजेता स्टार्टअप्स को ₹3.5 लाख का सीड ग्रांट तथा उपविजेता स्टार्टअप्स को ₹2.2 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।





Ques: Which gold mine became India's only operational private-sector primary gold mine since Independence after commencing commercial operations in 2026?

प्रश्न: वर्ष 2026 में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की एकमात्र परिचालित निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान कौन-सी बनी?

- A) Hutti Gold Mine / हट्टी स्वर्ण खदान
- B) Kolar Gold Fields / कोलार गोल्ड फील्ड्स
- C) Jonnagiri Gold Mine / जोन्नागिरि स्वर्ण खदान
- D) Ramagiri Gold Mine / रामगिरि स्वर्ण खदान
- E) Sonbhadra Gold Mine / सोनभद्र स्वर्ण खदान

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Jonnagiri Gold Mine in Tuggali Mandal, Kurnool district, Andhra Pradesh, commenced commercial operations.
- आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के तुगगली मंडल स्थित जोन्नागिरि स्वर्ण खदान ने वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।
- The mine is operated by Geomysore Services India Pvt. Ltd. and is described as India's only operational private-sector primary gold mine since Independence.
- इस खदान का संचालन Geomysore Services India Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है और इसे स्वतंत्रता के बाद भारत की एकमात्र परिचालित निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान बताया गया है।
- The project covers an area of about 598 hectares and involves an investment of ₹405 crore.
- यह परियोजना लगभग 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है तथा इसमें ₹405 करोड़ का निवेश किया गया है।
- The mine is located in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh, where Kurnool is one of the state's major mineral-bearing districts.
- यह खदान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कुरनूल राज्य के प्रमुख खनिज संपन्न जिलों में से एक है।
- The mine is expected to produce around 400 kg of gold in 2026–27, with annual production projected to increase to 1,000 kg in subsequent years and 2 tonnes after further expansion.





Ques: Prime Minister Narendra Modi will attend the Golden Jubilee National Day celebrations of which country as the Guest of Honour in June 2026?

प्रश्न: जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के गोल्डन जुबली राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे?

- A) Mauritius / मॉरीशस
- B) Seychelles / सेशेल्स
- C) Maldives / मालदीव
- D) Sri Lanka / श्रीलंका
- E) Madagascar / मेडागास्कर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi will undertake a State Visit to Seychelles from 27–29 June 2026.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।
- PM Modi will attend the Golden Jubilee celebrations of Seychelles' National Day as the Guest of Honour.
- प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
- The visit highlights the close and friendly relations between India and Seychelles.
- यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है।
- India and Seychelles maintain strong cooperation in maritime security, defence, development partnership, capacity building and the blue economy.
- भारत और सेशेल्स के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण तथा ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है।
- The visit is expected to further strengthen bilateral ties and enhance cooperation in the Indian Ocean Region (IOR).
- इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सहयोग बढ़ेगा।
- Seychelles is an important maritime partner of India in the Western Indian Ocean region.
- पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार है।





About Seychelles | सेशेल्स के बारे में

- Seychelles is an island nation located in the Indian Ocean, northeast of Madagascar.
- सेशेल्स हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है।
- It is a member of the Commonwealth of Nations and several regional organizations.
- यह राष्ट्रमंडल (Commonwealth) तथा कई क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है।
- The country is known for its strategic location in the Indian Ocean and rich marine biodiversity.
- यह देश हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति एवं समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

Static GK

- Capital of Seychelles – Victoria
- सेशेल्स की राजधानी – विक्टोरिया
- Currency – Seychellois Rupee (SCR)
- मुद्रा – सेशेलोइस रुपया (SCR)
- President of Seychelles – Patrick Herminie
- सेशेल्स के राष्ट्रपति – पैट्रिक हर्मिनी
- Official Languages – English, French and Seychellois Creole
- आधिकारिक भाषाएँ – अंग्रेज़ी, फ्रेंच एवं सेशेलोइस क्रियोल
- Independence Day / National Day – 29 June
- स्वतंत्रता दिवस / राष्ट्रीय दिवस – 29 जून





Ques: Which organization has successfully completed the first cohort of its flagship startup acceleration programme BHARATI?

प्रश्न: BHARATI नामक अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेशन कार्यक्रम का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा करने वाला संगठन कौन-सा है?

- A) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) / कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
- B) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- C) Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) / भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
- D) Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) / लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)
- E) National Horticulture Board (NHB) / राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) successfully completed the first cohort of its flagship startup acceleration programme BHARATI.
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेशन कार्यक्रम BHARATI का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा किया।
- The inaugural cohort included 100 startups from 22 States and 2 Union Territories.
- पहले बैच में 22 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 100 स्टार्टअप शामिल थे।
- Out of these, 68 startups were from the agri-food products sector.
- इनमें से 68 स्टार्टअप कृषि-खाद्य (Agri-food) उत्पाद क्षेत्र से संबंधित थे।
- The initiative aims to promote innovation-driven growth in India's agri-food export sector.
- इस पहल का उद्देश्य भारत के कृषि-खाद्य निर्यात क्षेत्र में नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना है।
- The programme supports APEDA's target of achieving USD 50 billion exports of APEDA-scheduled products by 2030.
- यह कार्यक्रम 2030 तक APEDA-अनुसूचित उत्पादों के 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।





- BHARATI stands for Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Innovation and is designed to help Indian agri-food startups become successful exporters.
- BHARATI का पूर्ण रूप Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Innovation है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स को सफल निर्यातक बनने में सहायता प्रदान करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Established – 1986
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना – 1986
- APEDA Headquarters – New Delhi
- APEDA का मुख्यालय – नई दिल्ली
- APEDA functions under the Ministry of Commerce and Industry.
- APEDA वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- APEDA is responsible for the promotion and development of exports of scheduled agricultural and processed food products from India.
- APEDA भारत से अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के लिए उत्तरदायी है।
- Target for 2030 – USD 50 billion exports of APEDA-scheduled products.
- 2030 का लक्ष्य – APEDA-अनुसूचित उत्पादों का 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात।





Ques: Which company launched the world's first Sub-1 Nanometer chip technology?

प्रश्न: दुनिया की पहली Sub-1 Nanometer चिप तकनीक किस कंपनी ने लॉन्च की?

- A) Intel / इंटेल
- B) IBM / आईबीएम
- C) NVIDIA / एनवीडिया
- D) Qualcomm / क्वालकॉम
- E) AMD / एएमडी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- IBM unveiled the world's first Sub-1 Nanometer semiconductor chip technology featuring a transistor architecture of 0.7 nanometers (7 angstroms).
- IBM ने 0.7 नैनोमीटर (7 एंग्स्ट्रॉम) ट्रांजिस्टर आर्किटेक्चर वाली दुनिया की पहली Sub-1 Nanometer सेमीकंडक्टर चिप तकनीक पेश की।
- The breakthrough is aimed at meeting the growing computational demands of Artificial Intelligence (AI), High-Performance Computing (HPC) and advanced data processing.
- यह उपलब्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) और उन्नत डेटा प्रोसेसिंग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।
- The new chip technology can potentially deliver higher performance while consuming significantly less power than existing semiconductor technologies.
- यह नई चिप तकनीक मौजूदा सेमीकंडक्टर तकनीकों की तुलना में कम ऊर्जा खपत के साथ बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकती है।
- Smaller transistor sizes allow more transistors to be packed into a chip, improving speed, efficiency and processing capability.
- छोटे ट्रांजिस्टर आकार के कारण एक चिप में अधिक ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं, जिससे गति, दक्षता और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती है।
- The innovation strengthens IBM's position in advanced semiconductor research and next-generation computing technologies.





- यह नवाचार उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग तकनीकों में IBM की स्थिति को और मजबूत बनाता है।
- The development comes amid intense global competition among technology companies to build more powerful AI-focused processors.
- यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक तकनीकी कंपनियों के बीच अधिक शक्तिशाली AI-केंद्रित प्रोसेसर विकसित करने की प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है।

About Nanometer Chip Technology | नैनोमीटर चिप तकनीक के बारे में

- A nanometer (nm) is one-billionth of a meter and is used to measure semiconductor transistor sizes.
- नैनोमीटर (nm) एक मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है और इसका उपयोग सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के आकार को मापने के लिए किया जाता है।
- Generally, smaller process nodes improve chip performance, energy efficiency and transistor density.
- सामान्यतः छोटे प्रोसेस नोड चिप के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और ट्रांजिस्टर घनत्व को बेहतर बनाते हैं।
- One nanometer equals 10 angstroms; therefore, 0.7 nm is equivalent to 7 angstroms.
- एक नैनोमीटर 10 एंग्स्ट्रॉम के बराबर होता है, इसलिए $0.7 \text{ nm} = 7 \text{ एंग्स्ट्रॉम}$ होता है।
- Advanced semiconductor technology is considered critical for AI, cloud computing, smartphones, supercomputers and defense applications.
- उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन, सुपरकंप्यूटर और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

Static GK

- IBM Established – 1911
- IBM की स्थापना – 1911
- Headquarters – Armonk, New York, USA
- मुख्यालय – आर्मोक, न्यूयॉर्क, अमेरिका
- CEO – Arvind Krishna
- CEO – अरविंद कृष्ण





Ques: Under the proposed amendment to the National Food Security Act (NFSA), how much foodgrain will each eligible person under Antyodaya Anna Yojana (AAY) receive per month?

प्रश्न: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितना खाद्यान्न मिलेगा?

- A) 5 kg / 5 किग्रा
- B) 6 kg / 6 किग्रा
- C) 7 kg / 7 किग्रा
- D) 10 kg / 10 किग्रा
- E) 35 kg / 35 किग्रा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Government has proposed amendments to the National Food Security Act (NFSA), 2013.
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
- The proposed amendment changes the foodgrain allocation system under the Antyodaya Anna Yojana (AAY).
- प्रस्तावित संशोधन के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में खाद्यान्न आवंटन व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
- Under the new proposal, every eligible person in an AAY household will receive 7 kg of foodgrains per month.
- नए प्रस्ताव के अनुसार AAY परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा।
- The total allocation for a household will be capped at a maximum of 35 kg per month.
- किसी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह ही मिलेगा।
- Earlier, every AAY household received a fixed 35 kg of foodgrains per month irrespective of family size.
- पहले प्रत्येक AAY परिवार को परिवार के आकार की परवाह किए बिना 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह मिलता था।
- The government stated that the change aims to remove inequalities in foodgrain distribution and ensure a more rational allocation system.





- सरकार के अनुसार यह बदलाव खाद्यान्न वितरण में असमानताओं को दूर करने तथा अधिक तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
- The draft amendment has been placed in the public domain and comments have been invited till 13 July.
- मसौदा संशोधन को सार्वजनिक किया गया है तथा 13 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

Old vs New System | पुरानी एवं नई व्यवस्था

- Old Rule: Every AAY household received 35 kg foodgrains per month irrespective of family size.
- पुराना नियम: प्रत्येक AAY परिवार को परिवार के आकार की परवाह किए बिना 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता था।
- New Rule: Each person will receive 7 kg foodgrains per month, subject to a maximum household limit of 35 kg.
- नया नियम: प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, लेकिन परिवार के लिए अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम होगी।
- Smaller families may receive less than 35 kg, while larger families will continue to receive up to 35 kg.
- छोटे परिवारों को 35 किलोग्राम से कम मिल सकता है, जबकि बड़े परिवारों को अधिकतम 35 किलोग्राम तक मिलेगा।

Static GK

- National Food Security Act (NFSA) Enacted – 2013
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू – 2013
- Antyodaya Anna Yojana (AAY) Launched – 2000
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शुरू – 2000
- Ministry Responsible – Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
- संबंधित मंत्रालय – उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- Department Concerned – Department of Food and Public Distribution
- संबंधित विभाग – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- AAY is aimed at the poorest of poor households in India.
- AAY का उद्देश्य देश के सबसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।





Ques: What was India's global rank in the QS World Future Skills Index 2027?

प्रश्न: QS World Future Skills Index 2027 में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही?

- A) 10th / 10वाँ
- B) 11th / 11वाँ
- C) 13th / 13वाँ
- D) 15th / 15वाँ
- E) 18th / 18वाँ

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The QS World Future Skills Index 2027, published by QS (London), assessed 89 countries on their preparedness for future skills and workforce transformation.
- QS (लंदन) द्वारा प्रकाशित QS World Future Skills Index 2027 में भविष्य के कौशल एवं कार्यबल परिवर्तन की तैयारी के आधार पर 89 देशों का मूल्यांकन किया गया।
- India secured the 13th position globally with an overall score of 89.4 out of 100.
- भारत ने 100 में से 89.4 अंक प्राप्त करते हुए वैश्विक स्तर पर 13वाँ स्थान हासिल किया।
- India ranked 1st in the South Asia region and was the only South Asian country to feature among the top 15 in the index.
- भारत दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर रहा तथा शीर्ष 15 में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश बना।
- The United States of America (USA) topped the overall rankings with a score of 99.2.
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने 99.2 अंक के साथ समग्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया।
- The index evaluated countries on four indicators: Skills Alignment, Academic Readiness, Future of Work, and Economic Transformation.
- इस सूचकांक में देशों का मूल्यांकन चार संकेतकों के आधार पर किया गया: Skills Alignment, Academic Readiness, Future of Work तथा Economic Transformation।
- Ranking of India in different indicators: Skills Alignment (18), Academic Readiness (22), Future of Work (5), Economic Transformation (14)
- अलग-अलग पैमानों पर भारत की रैंकिंग: स्किल्स अलाइनमेंट (18), एकेडमिक तैयारी (22), काम का भविष्य (5), आर्थिक बदलाव (14)





Ques: What is the bilateral trade target set by India and Russia to be achieved by 2030?

प्रश्न: भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है?

- A) USD 75 Billion / 75 अरब डॉलर
- B) USD 80 Billion / 80 अरब डॉलर
- C) USD 90 Billion / 90 अरब डॉलर
- D) USD 100 Billion / 100 अरब डॉलर
- E) USD 120 Billion / 120 अरब डॉलर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India and Russia are working to further strengthen their economic and trade relations with a target of achieving USD 100 billion in bilateral trade by 2030.
- भारत और रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ अपने आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर कार्य कर रहे हैं।
- Kremlin spokesperson Dmitry Peskov stated that bilateral trade between the two countries is already witnessing a steady upward trend.
- क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- The current trade volume between India and Russia stands at approximately USD 60 billion.
- भारत और रूस के बीच वर्तमान व्यापार लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है।
- Peskov described India as one of the fastest-growing economies in the world and emphasized its vast economic potential.
- पेसकोव ने भारत को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया तथा इसकी विशाल आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला।
- He termed India-Russia ties a “Privileged Strategic Partnership” built on mutual trust and long-term cooperation.
- उन्होंने भारत-रूस संबंधों को आपसी विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित “विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Privileged Strategic Partnership)” बताया।





India–Russia Relations | भारत–रूस संबंध

- India and Russia maintain a long-standing strategic partnership covering defence, energy, trade, space and technology sectors.
- भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी सहित अनेक क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है।
- Both countries are members of BRICS, SCO and other important international forums.
- दोनों देश BRICS, SCO तथा अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंचों के सदस्य हैं।
- Bilateral trade has expanded significantly in recent years, particularly in energy and commodity sectors.
- हाल के वर्षों में विशेष रूप से ऊर्जा एवं वस्तु (Commodity) क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

Static GK

- Capital of Russia – Moscow
- रूस की राजधानी – मॉस्को
- Currency of Russia – Russian Ruble
- रूस की मुद्रा – रूसी रूबल
- President of Russia – Vladimir Putin
- रूस के राष्ट्रपति – व्लादिमीर पुतिन
- BRICS Members – Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia and Indonesia
- BRICS के सदस्य – ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया





Ques: What was the theme of the 11th BRICS Energy Ministers' Meeting hosted by India under its BRICS Chairship 2026?

प्रश्न: भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत आयोजित 11वीं BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का विषय (Theme) क्या था?

- A) Green Energy for Future / भविष्य के लिए हरित ऊर्जा
- B) Energy Security and Sustainability / ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास
- C) Clean Energy, Clean Planet / स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ग्रह
- D) Renewable Energy for Growth / विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा
- E) Energy for All / सभी के लिए ऊर्जा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- India hosted the 11th BRICS Energy Ministers' Meeting in Gurugram, Haryana, under its BRICS Chairship 2026.
- भारत ने अपनी BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- Energy Ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries participated in the meeting.
- इस बैठक में BRICS के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- The theme of the Energy Track was "Energy for All."
- ऊर्जा ट्रैक का विषय "Energy for All (सभी के लिए ऊर्जा)" था।
- India has set an ambitious target of achieving 410 GWh of energy storage capacity by 2032.
- भारत ने 2032 तक 410 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- This was India's fourth BRICS Chairship, after its previous chairships in 2012, 2016, and 2021.
- यह भारत की चौथी BRICS अध्यक्षता थी। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में BRICS की अध्यक्षता कर चुका है।





Recent News Headlines Related to Summits / conference

- India's National Security Adviser (NSA) Ajit Doval hosted the meeting of National Security Advisers (NSAs) of BRICS countries in New Delhi. India's 2026 BRICS Chairship is being conducted under the theme "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability."
- भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की बैठक की मेज़बानी की। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) की थीम के तहत आयोजित की जा रही है।
- Union Home Minister Amit Shah chaired a meeting in New Delhi where six states reached a consensus on the long-pending Kishau Multi-Purpose Dam Project.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें छह राज्यों ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना पर सहमति व्यक्त की।
- The 16th BRICS Agriculture Ministers' Meeting was held on 12–13 June 2026 in Indore under India's BRICS Presidency.
- 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 12–13 जून 2026 को इंदौर, मध्य प्रदेश में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई।
- The 13th BRICS Urbanisation Forum was held in Sushma Swaraj Bhavan, New Delhi, from 11–12 June 2026 under India's BRICS Chairship 2026.
- 13वां BRICS शहरीकरण फोरम भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत 11–12 जून 2026 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- The 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog was held at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The theme of the meeting was "Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047." During the meeting, Prime Minister Narendra Modi called for increasing the number of Lakhpati Didis from 3 crore to 6 crore.
- नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित की गई। बैठक का विषय "विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास" था। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लखपति दीदियों' की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का आह्वान किया।





Ques: Through which pass is India–China border trade set to resume after nearly six years?

प्रश्न: लगभग छह वर्षों बाद भारत–चीन सीमा व्यापार किस दर्रे के माध्यम से पुनः शुरू होने जा रहा है?

- A) Nathu La Pass / नाथू ला दर्रा
- B) Shipki La Pass / शिपकी ला दर्रा
- C) Lipulekh Pass / लिपुलेख दर्रा
- D) Jelep La Pass / जेलेप ला दर्रा
- E) Bum La Pass / बुम ला दर्रा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Border trade between India and China through the Lipulekh Pass in Uttarakhand is set to resume after a gap of nearly six years.
- उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत–चीन सीमा व्यापार लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रहा है।
- According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Taklakot market in Tibet.
- पिथौरागढ़ जिले के धारचूला प्रशासन के अनुसार भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत के तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा।
- A total of 26 trade passes have been issued to facilitate the resumption of cross-border trade.
- सीमा व्यापार को पुनः शुरू करने के लिए कुल 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं।
- Lipulekh Pass serves as an important trade route between India and the Tibet Autonomous Region of China.
- लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है।
- The reopening of border trade is expected to boost economic activities and livelihoods of local traders in the border region.
- सीमा व्यापार के पुनः आरंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियों और आजीविका को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- The route is also significant for the Kailash Mansarovar Yatra and strategic connectivity in the Himalayan region.





Ques: Where was the 90-kg bronze statue of Maharshi Sushruta unveiled in 2026?

प्रश्न: वर्ष 2026 में महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया?

- A) Royal College of Physicians, London / रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन
- B) University of Oxford, United Kingdom / ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम
- C) University of Glasgow, Scotland / ग्लासगो विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड
- D) Royal College of Surgeons of Edinburgh, Scotland / रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड
- E) King's College London / किंग्स कॉलेज लंदन

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- A 90-kilogram bronze statue of Maharshi Sushruta was unveiled at the Royal College of Surgeons of Edinburgh, Scotland, United Kingdom.
- महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्कॉटलैंड (यूनाइटेड किंगडम) के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में किया गया।
- The statue was installed in the Playfair Auditorium of the college, which was established in 1505 and is one of the oldest surgical institutions in the world.
- इस प्रतिमा को कॉलेज के प्लेफेयर ऑडिटोरियम में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1505 में हुई थी और यह विश्व के सबसे पुराने शल्य चिकित्सा संस्थानों में से एक है।
- The statue was donated by the Cheruvu Family Foundation, established by UK-based surgeon Professor Chandra Cheruvu and his family.
- यह प्रतिमा चेरुवु फैमिली फाउंडेशन द्वारा दान की गई, जिसकी स्थापना ब्रिटेन स्थित सर्जन प्रोफेसर चंद्रा चेरुवु और उनके परिवार ने की है।
- The bronze sculpture was crafted by an artist from Tiruvannamalai, Tamil Nadu.
- इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के एक कलाकार द्वारा किया गया।
- On the same occasion, Professor Chandra Cheruvu released a book titled "Maharshi Sushruta: A Compendium – Father of Surgery."
- इसी अवसर पर प्रोफेसर चंद्रा चेरुवु ने "Maharshi Sushruta: A Compendium – Father of Surgery" नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।





Ques: Which organic fertilizer brand has been launched by the Adani Group using agricultural waste?

प्रश्न: कृषि अपशिष्ट से निर्मित अडानी समूह द्वारा लॉन्च किए गए जैविक उर्वरक ब्रांड का नाम क्या है?

- A) Green Kranti / ग्रीन क्रांति
- B) Harit Amrit / हरित अमृत
- C) Bio Shakti / बायो शक्ति
- D) Organic Bharat / ऑर्गेनिक भारत
- E) Kisan Urja / किसान ऊर्जा

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Adani Group has expanded its presence in the organic fertilizer sector through its new brand, Harit Amrit.
- अडानी समूह ने अपने नए ब्रांड 'हरित अमृत' के माध्यम से जैविक उर्वरक क्षेत्र में प्रवेश किया है।
- The organic fertilizer is produced from agricultural waste and cattle dung through an integrated waste-to-energy model.
- यह जैविक उर्वरक कृषि अपशिष्ट एवं पशु गोबर से एकीकृत वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल के माध्यम से तैयार किया जाता है।
- The initiative is being implemented by Adani TotalEnergies Biomass Limited (ATBL), a subsidiary of Adani Total Gas Limited.
- इस पहल को अडानी टोटलएनर्जीज बायोमास लिमिटेड (ATBL) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
- Harit Amrit sales have expanded across Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat.
- हरित अमृत की बिक्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात तक विस्तारित की गई है।
- The company sold more than 4,575 tonnes of organic fertilizer during FY26, more than double the previous year's sales.
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 4,575 टन से अधिक जैविक उर्वरक की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है।
- The project supports sustainable agriculture by converting agricultural waste into valuable farm inputs.





- यह परियोजना कृषि अपशिष्ट को उपयोगी कृषि उत्पादों में बदलकर सतत कृषि को बढ़ावा देती है।
- It also helps reduce stubble burning and promotes renewable energy generation through compressed biogas (CBG).
- यह पराली जलाने की समस्या को कम करने के साथ-साथ संपीड़ित बायोगैस (CBG) के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है।

About Harit Amrit Project | हरित अमृत परियोजना के बारे में

- The flagship project is located at Barsana in Mathura district of Uttar Pradesh.
- प्रमुख परियोजना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में स्थित है।
- It is being developed as India's largest agriculture waste-based Compressed Biogas (CBG) facility.
- इसे भारत की सबसे बड़ी कृषि अपशिष्ट आधारित संपीड़ित बायोगैस (CBG) परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- The facility processes agricultural residue and cattle dung to produce biogas and organic fertilizer.
- यह संयंत्र कृषि अवशेष एवं पशु गोबर से बायोगैस तथा जैविक उर्वरक का उत्पादन करता है।
- The project contributes to waste management, clean energy generation and sustainable farming practices.
- यह परियोजना अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है।

Static GK

- Adani Group Founder & Chairman – Gautam Adani
- अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष – गौतम अडानी
- Adani Total Gas Limited Headquarters – Ahmedabad, Gujarat
- अडानी टोटल गैस लिमिटेड का मुख्यालय – अहमदाबाद, गुजरात
- Compressed Biogas (CBG) is a renewable fuel produced from organic waste.
- संपीड़ित बायोगैस (CBG) एक नवीकरणीय ईंधन है जो जैविक अपशिष्ट से तैयार किया जाता है।
- SATAT Scheme Launched – 2018
- SATAT योजना शुरू – 2018





Ques: Which state became the sixth state in India to be declared fully literate under the Ullas – Nav Bharat Saaksharta Karyakram (New India Literacy Programme)?

प्रश्न: उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme) के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का छठा राज्य कौन-सा बना?

- A) Sikkim / सिक्किम
- B) Goa / गोवा
- C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- D) Uttarakhand / उत्तराखंड
- E) Tripura / त्रिपुरा

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Uttarakhand declared itself a fully literate state under the Ullas – Nav Bharat Saaksharta Karyakram (New India Literacy Programme).
- उत्तराखंड ने उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme) के तहत स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया।
- Uttarakhand became the sixth state in India to achieve this milestone with a literacy rate of 98% or above.
- 98% या उससे अधिक साक्षरता दर के साथ उत्तराखंड पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का छठा राज्य बना।
- Before Uttarakhand, Mizoram, Goa, Tripura, Himachal Pradesh and Sikkim had already been declared fully literate.
- उत्तराखंड से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका था।
- Ladakh became the first Union Territory to be fully certified under the scheme.
- लद्दाख इस योजना के तहत पूर्ण साक्षर प्रमाणित होने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बना।
- Under the Ullas – Nav Bharat Saaksharta Karyakram, a state attains full literacy status when it achieves an adult literacy rate of at least 95% among people aged 15 years and above, while ensuring education for all non-literate individuals.





Ques: How many infrastructure projects were reviewed by Prime Minister Narendra Modi during the 52nd PRAGATI meeting?

प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI की 52वीं बैठक में कितनी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की?

- A) Two / दो
- B) Three / तीन
- C) Four / चार
- D) Five / पाँच
- E) Six / छह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) at Seva Teerth, New Delhi.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- During the meeting, he reviewed four major infrastructure projects across the Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors.
- बैठक के दौरान उन्होंने सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक गलियारा तथा मेट्रो रेल क्षेत्रों की चार प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की।
- These projects are spread across four States and involve an estimated investment of around ₹30,000 crore.
- ये परियोजनाएं चार राज्यों में फैली हुई हैं तथा इनमें लगभग ₹30,000 करोड़ का निवेश शामिल है।
- The Prime Minister emphasized timely completion of infrastructure projects to accelerate economic growth and improve public service delivery.
- प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास को गति देने तथा जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर बल दिया।
- PM Modi also reviewed progress related to AI-driven Tuberculosis (TB) elimination initiatives.
- प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित क्षयरोग (TB) उन्मूलन पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की।





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

The Indori Malwi potato received the Geographical Indication tag after notification by the Registrar of Geographical Indication, Chennai. Garadu tuber and balam cucumber from Ratlam district also received GI certification along with the Indori Malwi potato.

France is set to witness the historic inauguration of its first traditional Hindu temple and it is scheduled for September 2026. This announcement was made by the members of the Indian diaspora in France.

Five-time World Chess Champion Viswanathan Anand was honoured with the prestigious Sports Journalists' Federation of India (SJFI) Medal at a ceremony held at the Madras Cricket Club, Chennai. Anand is currently the Deputy President of FIDE.

The Centre for Development of Telematics, the telecom R&D centre under the Department of Telecommunications (DOT), signed an MoU with IIT Hyderabad to establish a Centre of Excellence (CoE) in Advanced Communication Technologies. This is the 4th CoE established by C-DOT. Previous CoEs are located at IIT Kanpur, IIT Gandhinagar, IIT Roorkee.

Comptroller and Auditor General (CAG) of India and the Supreme Audit Institution (SAI) of Israel signed MOU for Enhancing cooperation in public sector auditing.





महत्वपूर्ण वन-लाइनर करंट अफेयर्स

चेन्नई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) रजिस्ट्रार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, 'इंदौरी मालवी आलू' को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला है। इंदौरी मालवी आलू के साथ-साथ रतलाम जिले के 'गराडू कंद' और 'बालम खीरे' को भी GI सर्टिफिकेशन मिला है।

फ्रांस में अपने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन होने जा रहा है, जो सितंबर 2026 में होगा। यह घोषणा फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने की।

पांच बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद को चेन्नई के मद्रास क्रिकेट क्लब में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित 'स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SJFI) मेडल' से सम्मानित किया गया। आनंद अभी FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DOT) के तहत आने वाले टेलीकॉम R&D सेंटर, 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स' (C-DOT) ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ एक MoU पर साइन किए। यह C-DOT द्वारा स्थापित चौथा CoE है। इससे पहले के CoE IIT कानपुर, IIT गांधीनगर और IIT रुड़की में स्थापित किए गए हैं।

भारत के 'कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल' (CAG) और इज़राइल की 'सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन' (SAI) ने पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MoU पर साइन किए।

